

राजस्थान सरकार
नगरिय विकास विभाग

क्रमांक: प. 53/नविचि/3/99/पाट

जयपुर, दिनांक: 6/7/02

आदेश

राजस्थान विधिया [संगोपन] अधिनियम, 1999 को दिनांक 17.6.99 से प्रभावशाली है के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संगोपन कर धारा 90 को का समावेश किया गया है उक्त प्रावधान के द्वारा दिनांक 17.6.99 के पूर्व किये गये कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के परिणामस्वरूप भूमि राज्य सरकार को समर्पित कर उसके विपणन करने का प्रावधान है। राजस्थान कायन्तकारी अधिनियम 1955 को धारा 42 [बी] में अनुसूचित जाति/जनजाति को भूमियों के विधिया अधिनियम, 1999 के द्वारा राजस्थान कायन्तकारी अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों को अतिरिक्त कर दिया गया है एवं इस संबंध में विभाग के आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 1999 के द्वारा स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। अतः राजस्थान विधिया [संगोपन] अधिनियम, 1999 के प्रभावशाली होने से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति को भूमियों के गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को किये गये कृषि प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण के मामलों में विभाग के आदेश दिनांक 4 दिसम्बर, 1999 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं, तदनुसार कार्यवाही को पाले।

आज्ञा है

हो

[[एच. एन. भारद्वाज]]
मान्य उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशात्मक स्थानीय निकाय विभाग, राय. जयपुर

क्रमांक: भूमि/एफ. 7/प/डोरनको/02/10313-10501 दिनांक: 29/7/02
प्रतिनिर्देशन विभागाधिकारी को, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निर्देश [प्रोप] स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, बिकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त/अधिसूचक अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान।

K-P-T-0

अतिरिक्त के.आर.

(46)

(35)